पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1989 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1528

इस पर निर्णय लिया गयाः 17.04.1989

याचिकाकर्ताओंः **उमाधार प्रसाद सिंह**

बनाम

उत्तरदाताः बिहार राज्य और अन्य

भारत का संविधान-अनुच्छेद 178, 179, 212, 226-बिहार विधान सभा की कार्यवाही--याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या-2 पर आरोप लगाया। है कि ने वास्तव में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था और यह कि एक निश्चित इस्तीफे में हेरफेर किया गया था, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3, तत्कालीन उपाध्यक्ष को एक अधिसूचना मिली थी जिसमें घोषणा की गई थी कि अध्यक्ष का पद खाली हो गया था-इस आधार पर तत्काल आवेदन की स्थिरता पर आपत्ति, अन्य बातों के साथ-साथ कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 212 इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बिहार विधानसभा की कार्यवाही में प्रवेश करने से रोकता है-इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान विधानसभा ने एक नया अध्यक्ष एकत्रित किया था और चुना था अभिनिर्धारितः- रिट आवेदन में लगाये गये विवाद स्वतः ही नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए विधानसभा में की गई कार्रवाई को प्रभावित करेगा और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 212 के प्रतिबंध को आकर्षित करेगा-तथ्यों की जांच करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही कि जारी किया गया रिट प्रभावी रूप से विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप हो सकता है कि अदालतों ने एक रिट जारी करने से परहेज किया है-आवेदन खारिज कर दिया गया।

(कंडिका 2,3,4,6)

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1989 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1528

इस पर निर्णय लिया गयाः 17.04.1989

याचिकाकर्ताओंः **उमाधार प्रसाद सिंह**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य और अन्य**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

पी.एस. मिश्रा, यू.पी. सिंह और बी.के. रॉय, न्यायमूर्तिगण

अधिवक्तागणः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः रामचंद्र झा और सुबोध कुमार झा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः जे.एन. पांडे, अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता बी.एन. मिश्रा, अतिरिक्त/अपर महाधिवक्ता के जे.सी. और एम.के. सिंह और मिहिर कुमार झा, अधिवक्तागण

मध्यस्थ के लिएः अशोक कुमार केशरी, राकेश रंजन प्रसाद और जय शाकेर बर्नवाल, अधिवक्तागण

आदेश

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और मध्यस्थ के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना। याचिकाकर्ता और मध्यस्थ दोनों विधान सभा के सदस्य हैं।

2. अपने आवेदन में, जैसा कि हमारे सामने दायर किया गया है, याचिकाकर्ता ने उस प्रतिवादी संख्या-2 पर आरोप लगाया है। कि उसने वास्तव में बिहार सभा के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था और यह कि एक निश्चित इस्तीफे में हेरफेर किया

गया था, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3, तत्कालीन उपाध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें घोषणा की गई कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के इस्तीफे की स्वीकृति के कारण, अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। आवेदन में कुछ तथ्यों का उल्लेख या तो प्रत्यर्थी संख्या 2 की अनन्य जानकारी के भीतर या याचिकाओं की जानकारी में किया गया है जो यह सुझाव देते हैं कि यह मानने के लिए अच्छे कारण थे कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के इस्तीफे की स्वीकृति की अधिसूचना कानून और वास्तव में दोनों में दुर्भावनापूर्ण होने के कारण अमान्य है।

3. हालाँकि, हस्तक्षेपकर्ता ने मुख्य रूप से तत्काली आवेदन के रखरखाव पर इस आधार पर आपत्ति की है कि अन्य बातों के साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 212 इस न्यायालय की अधिकारिता को बिहार विधान सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से रोकता है और जब तक सदिन की कार्यवाही से संबंधित मुद्दों की जांच नहीं की जाती है। तब तक, याचिकाकर्ता के आवेदन पर कुछ नहीं कहा जा सका कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या नहीं।

4. अपर/अतिरिक्त। महाधिवक्ता ने इसमें मध्यस्थ के तर्क का सटीक समर्थन किया है और इसके बाद की एक घटना को हमारे ध्यान में लाया है। इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान विधानसभा ने बैठक की और एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया। इस प्रकार, आज हम रिट आवेदन में कथित विवाद में प्रवेश करना नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए विधानसभा में की गई कार्रवाई को सहज रूप से प्रभावित करेगी और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 212 के प्रतिबंध को आकर्षित करेगी, हम इस संबंध में विद्वान अतिरिक्त न्यायाधीश के तर्क से सहमत हैं। जैसा कि आज यह नहीं कहा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही की वैधता या अन्यथा की जांच किए बिना उत्प्रेषण या अधिकार पृच्छा की प्रकृति में एक रिट और एक परमादेश जारी किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 को

अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर वापस लाया जाएगा। उक्त कारण से आवेदन फलहीन हो गया है, और यदि वास्तव में फलहीन नहीं है, तो अनुच्छेद 212 के तहत वर्जित है।

5. हम रिट याचिका के विचारणीयता के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क के बारे में एक या दूसरे तरीके से नहीं कहते हैं कि-क्या यह मूल रुप से तैयार किया गया था या जैसा की मध्यस्थ की आपत्ति है कि मूल रुप से तैयार किया गया था पर धारणीय। विचारणीय नहीं था और भारतीय संविधान की धारा 212 के अंतर्गत प्रतिबंध को आकर्षित करता है। भारतीय संविधान की धारा 178,179 और 212 के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 208 के तहत उस पर बने नियमों के परीक्षण किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होगा।

6. भारत में अदालतों को कई बार विधान सभा के मामलों को छूने वाले कार्यों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय की शक्ति की सीमाओं और उसके अनुच्छेद 212 के तहत प्रतिबंध की सीमा का निर्णय करने संबंधी में पेचीदा सवालों का सामना करना पड़ा है। तथ्यों की जांच करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही कि जारी की गई रिट प्रभावी रूप से विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप हो सकती है, अदालतों ने रिट जारी करने से परहेज किया है। हालाँकि, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका संक्षिप्त उत्तर तत्काल आवेदन में नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, जब से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, आज के रूप में, यह आवेदन फलहीन हो गया है, हम आवेदन को खारिज करते हैं।

7. हमने दुर्भावनापूर्ण आरोपों की जांच नहीं की है, यह न कहें कि वे सही हैं।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।